बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 204 ● नई दिल्ली ● शनिवार 30 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ाई, लाखों टीचर्स को राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हजारों शिक्षकों को राहत देते हुए टीईटी पास करने की डेडलाइन एक सालके लिए बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। पहले यह समयसीमा 31 अगस्त 2027 थी। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए राहत भरा है जिन्होंने अभी तक परीक्षा पास नहीं की है। कोर्ट के इस निर्णय से विशेष रूप से उन राज्यों में तनाव कम होने की उम्मीद है जहां बड़ी संख्या में शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाए थे। शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग को खारिज कर दिया गया है।

आज भारत आएंगे म्यांमार के राष्ट्रपति, व्यापार और सीमा सुरक्षा पर होगी अहम चर्चा

नई दिल्ली । म्यांमार के राष्ट्रपति आज यानी 30 मई से चार दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को भारत-म्यांमार संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रपति 2 जून तक भारत में रहेंगे और दिल्ली, बोधगया तथा मुंबई का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। ऐसे समय में यह दौरा हो रहा है, जब भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा, सीमा संपर्क और एक्ट ईस्ट नीति को नई मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार भारत के लिए केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंच का अहम द्वार भी माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और सभ्यतागत रिश्तों से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत और म्यांमार करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों में म्यांमार की भूमिका अहम मानी जाती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सड़क, बंदरगाह और व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारत की कोशिश है कि म्यांमार के जरिए दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों तक आर्थिक पहुंच और मजबूत हो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश अपने पुराने ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दौरे के दौरान व्यापार और निवेश बढ़ाने पर

भी विशेष जोर रहेगा।

व्यापार और निवेश पर भी रहेगा फोकस?

म्यांमार राष्ट्रपति की यात्रा में व्यापारिक बैठकों को भी खास महत्व दिया गया है। राष्ट्रपति मुंबई में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि भारत म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों की कोशिश आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की है। भारत पहले से ही म्यांमार में कई विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सके।

म्यांमार दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी उठा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से म्यांमार शरणार्थियों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर भी सवाल पूछा गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सीधे टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह साफ किया कि यह एक आधिकारिक यात्रा है और भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए तैयार है। भारत की कोशिश यह संदेश देने की है कि दोनों देशों के रिश्ते किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित हैं। बोधगया दौरे को भी इसी सांस्कृतिक जुड़ाव का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है।

क्यों अहम माना जा रहा है यह दौरा?

माना जा रहा है कि ऐसे समय में हो रही है जब दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भू-राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। पश्चिम एशिया संकट, चीन की सक्रियता और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार राष्ट्रपति की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सीएम रेखा एक्शन में, राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण, मिलीं कई कमियां

नई दिल्ली ।रोहिणी के राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण अंबेडकर भवन, रोहिणी में स्थित कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) और VI-C (रोहिणी) में हुआ। इस दौरान कार्यालयों में कई नागरिक सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई गईं। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज अंबेडकर भवन, रोहिणी में राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) एवं VI-C (रोहिणी) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां पाई गईं।

सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सुविधा के केंद्र हैं। नागरिकों को सम्मानजनक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है।उन्होंने सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर कर व्यवस्था में ठोस सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मिलीं गंभीर कमियां

निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया। कार्यालयों में स्वच्छता का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। शौचालयों की स्थिति भी खराब थी, जिससे आगंतुकों को परेशानी हो रही थी। प्रकाश व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। बैठने की पर्याप्त सुविधा का अभाव भी देखा गया, जिससे नागरिकों को इंतजार करने में दिक्कत हो रही थी।

सुधार के लिए निर्देश

निरीक्षण करने वाले अधिकारी ने सभी कमियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सुधार करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि व्यवस्था में ठोस बदलाव हों। सरकारी कार्यालयों को जनता के लिए बेहतर बनाना प्राथमिकता है। भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह भी साफ किया गया।

राहुल गांधी का दिल्ली में ऑटो चालकों संग लंच, बढ़ती ईंधन की कीमतों की सुनी चिंताएं

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मध्य दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों से मुलाकात की और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। यह अनौपचारिक बातचीत राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के उद्देश्य से की गई थी। राहुल गांधी ने बंगाली मार्केट के पास टोडरमल रोड पर लगभग आधा घंटा बिताया, जहां उन्होंने टोडरमल पार्क में जमा हुए चालकों से बातचीत की। इस दौरान, उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से सीधे बात की और बढ़ते खर्चों, ईंधन की कीमतों और घटती आय के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। इस बातचीत के तहत कांग्रेस सांसद को एक ऑटो चालक के साथ दोपहर का भोजन करते हुए भी देखा गया। यह बातचीत बंगाली मार्केट के पास टोडरमल पार्क में हुई, जो स्थानीय परिवहन कर्मचारियों और यात्रियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यस्त इलाका है। खबरों के अनुसार, राहुल गांधी ने ड्राइवरों से उनकी रोजमर्रा की कठिनाइयों और परिवहन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले वित्तीय दबावों के बारे में बातचीत की। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली और आसपास के शहरों में वाणिज्यिक वाहन संचालक बढ़ती परिचालन लागत और अपर्याप्त किराया संशोधन को लेकर चिंता जता रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में अक्सर इसी तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें उन्होंने श्रमिकों, मजदूरों, डिलीवरी कर्मियों और ड्राइवरों से मिलकर आजीविका संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। यह

बैठक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में परिवहन यूनियनों द्वारा 21 से 23 मई के बीच की गई व्यापक हड़ताल के कुछ ही दिनों बाद हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कैब और ऑटो-रिक्शा सहित कई सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुईं, जिससे एनसीआर भर के यात्रियों को असुविधा हुई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) के बैनर तले 68 से अधिक परिवहन यूनियनों ने चक्का जाम विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

उनके 17 राज्य बजट प्रभावशाली रहे-जयराम रमेश ने सिद्धारमैया की विरासत को सराहा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राज्य के राजनीतिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताते हुए उनकी प्रशासनिक कुशलता, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और चार दशकों के राजनीतिक जीवन में नेतृत्व परिवर्तन को गरिमापूर्ण ढंग से संभालने की प्रशंसा की। ठ्व पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि सिद्धारमैया का चार दशक लंबा राजनीतिक करियर और 17 राज्य बजट पेश करना कर्नाटक के शासन में उनके कद और योगदान को दर्शाता है। कांग्रेस महासचिव ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक

सोच को बढ़ावा देने के लिए सिद्धारमैया की प्रशंसा की। सिद्धारमैया राय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका करियर 2013-2018 और 2023-2026 के दो अलग-अलग कार्यकालों में 8 वर्षों से अधिक का रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि सिद्धारमैया चार दशकों से अधिक समय से कर्नाटक की राजनीति में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। रमेश ने कहा कि उन्होंने राय में 17 बजट पेश किए हैं, जो गुजरात में वजुभाई वाला द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से सिर्फ एक कम और पश्चिम बंगाल में डॉ. असीम दासगुप्ता द्वारा हासिल की गई उपलब्धि से एक अधिक है। उनके सभी 17 बजट उल्लेखनीय और प्रभावशाली रहे हैं। बजट बनाने और प्रशासन पर उनकी महारत के अलावा, सिद्धारमैया सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और परंपराओं के अटूट हिमायती और तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सोच के सशक्त समर्थक रहे हैं। कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के बीच, विधान सौधा में कर्मचारियों द्वारा सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के उपमुख्यमंत्री पद की नेमप्लेटें अलमारी में रखी जाती देखी गईं। इससे पहले, सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल, रायसभा चुनाव और अन्य संगठनात्मक मामलों पर चर्चा की।

दो महीने के भीतर अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त करे DERC; अदालत ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार की चयन समिति से कहा है कि वह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति दो महीने के भीतर सुनिश्चित करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने दिल्ली की भाजपा सरकार की उस अधिसूचना को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें तीन खाली पदों को भरने के लिए एक खोज और चयन समिति बनाने की बात कही गई है। यह समिति पिछले निर्देशों के पालन में 27 मई को बनाई गई थी। अदालत ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह दो महीने की अवधि में अध्यक्ष और दो सदस्यों का चुनाव पूरा करे। इसके साथ ही सरकार को दो महीने बाद एक अनुपालन हलफनामा भी दाखिल करना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। एनर्जी वॉचडॉग नामक एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रणव सचदेवा ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि ये नियुक्तियां एक महीने के भीतर की जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीईआरसी पिछले एक साल से कानूनी फैसले लेने का अपना काम नहीं कर पा रहा है। डीईआरसी दिल्ली में बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम बिजली की दरें तय करना, बिजली कंपनियों को लाइसेंस देना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह उपभोक्ताओं और बिजली प्रदाताओं के बीच विवादों को भी सुलझाता है। याचिका में कहा गया कि डीईआरसी की वर्तमान स्थिति कानून के खिलाफ है। इसमें केवल दो अस्थायी सदस्य काम कर रहे हैं। आयोग में न तो कोई अध्यक्ष है और न ही कोई कानूनी विशेषज्ञ सदस्य है।

पर्यटन को बढ़ावा

सड़कें विकास की रीढ़ होती है। किसी पिछड़े क्षेत्र में एक सड़क बन जाने से उस क्षेत्र का विकास स्वतः होने लगता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अवस्थापना सुविधाओं के विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एक्सप्रेस-वे नेटवर्क ने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य किया है। इन्हीं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की नई धुरी बनकर उभरा है। यह एक्सप्रेस-वे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वांचल के आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास का मजबूत आधार बन गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे लगभग 91.352 किलोमीटर लंबा प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेस-वे गोरखपुर बाईपास एनएच-27 पर ग्राम जैतपुर के पास से शुरू होकर जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ता है। यह परियोजना गोरखपुर, संतकबीरनगर, अंबेडकरनगर और आजमगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जनपदों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ती है। इस एक्सप्रेस-वे का 20 जून, 2025 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया। 01 अगस्त 2025 से इस एक्सप्रेस-वे पर टोल कलेक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके संचालन के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा प्राप्त हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लंबे समय तक बेहतर सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता रहा। यहां के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में अधिक समय लगता था, जिससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई समस्याएं बनी रहती थीं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे ने इस स्थिति को बदलने का कार्य किया है। अब गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से लखनऊ, वाराणसी तथा अन्य बड़े शहरों तक पहुंचना कहीं अधिक आसान और तेज हो गया है। यह एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़कर पूरे प्रदेश के एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस परियोजना के कारण गोरखपुर क्षेत्र सीधे राजधानी लखनऊ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बेहतर रूप से जुड़ गया है। इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे एक ग्रीन फील्ड परियोजना है। इसे नई भूमि पर आधुनिक तकनीक और बेहतर डिजाइन के साथ विकसित किया गया है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे होने के कारण इसमें मोड़ कम हैं, यातायात अधिक व्यवस्थित रहता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होती है। साथ ही वाहन बिना रुकावट के अधिक गति से चल सकते हैं, जिससे यात्रा समय में कम समय लगता है। यह एक्सप्रेस-वे आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सड़क, सुरक्षित पुल, सर्विस रोड, ड्रेनेज व्यवस्था और आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया गया है। उ0प्र0 का पूर्वांचल क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। लेकिन लंबे समय तक किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बनने से किसानों को अब अपने उत्पाद कम समय में बड़ी मंडियों तक पहुंचाने की सुविधा मिल रही है। इससे परिवहन लागत कम होगी और फसल खराब होने की संभावना भी घटेगी। विशेष रूप से सब्जी और डेयरी उत्पादों के व्यापार को इससे बड़ी गति मिलेगी। किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार एक्सप्रेस-वे केवल यातायात सुविधा के लिए नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे भी इसी सोच का हिस्सा है। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट हब और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों, कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इससे नई ऊर्जा मिलेगी। आने वाले समय में यह क्षेत्र निवेश और उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। जब किसी क्षेत्र में सड़क और आधारभूत संरचना मजबूत होती है तो वहां उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। भविष्य में एक्सप्रेस-वे के किनारे स्थापित होने वाले उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों से स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है। इससे पलायन की समस्या में भी कमी आएगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। बेहतर सड़क संपर्क का सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी मिलता है। अब पूर्वांचल के लोग कम समय में बड़े अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंच सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तेजी से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान होगा। साथ ही छात्र भी बड़े शहरों के शिक्षण संस्थानों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ मंदिर, कुशीनगर, संतकबीरनगर और आसपास के कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बेहतर सड़क संपर्क से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगी। इससे होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया गया है। यहां भोजन, शौचालय, पार्किंग, ईंधन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आने वाले समय में इन परिसरों के आसपास और भी सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बन सके। उत्तर प्रदेश तेजी से देश की आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेस-वे नेटवर्क इस विकास मॉडल का महत्वपूर्ण आधार है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, बल्कि निवेश, उद्योग, व्यापार और रोजगार को भी नई गति देते हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे ने यह साबित किया है कि मजबूत आधारभूत संरचना किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी कुंजी होती है। यह परियोजना पूर्वांचल के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह एक्सप्रेस-वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कान्स के रेड कार्पेट पर छाया पंजाबियों का जलवा

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रेड कार्पेट का बहुत प्रचलन है। रेड कार्पेट पर आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनियों के बीच फिल्म सितारे उतरते हैं तो कैमरों की फ्लैश उन्हें और भी चमकदार बना देती है। रेड कार्पेट यानी लाल कालीन का इतिहास बहुत पुराना है। 1821 में, दक्षिण कैरोलिना के जॉर्जटाउन में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के स्वागत के लिए एक लाल कालीन बिछाया गया था, जो आधुनिक परिवेश में किसी को लाल कालीन जैसा स्वागत देने के शुरुआती दर्ज उदाहरणों में से एक है। 1902 तक यह मुहावरा तब प्रचलन में आया जब न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड ने अपनी विलासितापूर्ण ट्रेन '20वीं सेंचुरी लिमिटेड' में सवार होने वाले यात्रियों के लिए लाल कालीन बिछाया। हॉलीवुड ने 1922 में ग्रौमन के इजिप्शियन थिएटर में 'रॉबिन हुड' के प्रीमियर के दौरान इस विचार को अपनाया। 1961 तक, एकेडमी अवॉर्ड्स ने अपने सितारों के आगमन के लिए एक आधिकारिक रेड कार्पेट की शुरुआत की, और इसी क्षण से यह ग्लैमर और समारोह का वैश्विक प्रतीक बन गया। रंग मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, लाल रंग हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यानी यह भीड़ में, तस्वीरों में और टीवी पर अलग दिखता है। आपकी निगाहें उत्साह और उत्सुकता के साथ रेड कार्पेट की ओर खिंची चली जाती हैं, यह देखने के लिए कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति इस पर चलेगा। रेड कार्पेट विशिष्ट अतिथियों के स्वागत का एक प्रतीकात्मक तरीका बना हुआ है और अब सेलिब्रिटी संस्कृति के तमाशे का केंद्र बन गया है। यदि आप रेड कार्पेट के फ्लो का आनंद लेते हैं, तो ध्यान दें कि कैसे लाल रंग तुरंत आंखों को आकर्षित करता है और उत्सुकता की भावना पैदा करता है। 1990 के दशक के मध्य में मिस वर्ल्ड/मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं को टेलीविजन पर लाइव देखना मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन था, घंटों तक चलने वाला दृश्य, जिसमें कई एलिमिनेशन राउंड, फैशन परेड, प्रश्नोत्तर सत्र और अंत में खुशी के आंसुओं के बीच सिंड्रेला का ताजपोशी होना शामिल था। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी आदि भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कान्स फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर हमेशा की तरह एश्वर्या राय, आलिया भट्ट और अन्य कई बालीवुड की हिरोइनों ने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है। कभी रेड कार्पेट पर बड़े सितारों का ही दबदबा देखने को मिलता था लेकिन इस बार पहली बार पंजाबी फिल्म उद्योग ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। पंजाबी फिल्मों की लोकप्रियअभिनेत्री रूपी गिल ने प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'चढ़दीकला' के प्रचार के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पंजाबी सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया। विश्व स्तर पर चर्चित इस कार्यक्रम में गिल की उपस्थिति पंजाबी सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पारंपरिक पंजाबी परिधान में सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे-धजे इस अभिनेत्री ने सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफार्मों में से एक पर एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत की।

गिल की पोशाक में आइवरी रंग का शरारा सेट शामिल था, जिसमें ऑफ-व्हाइट रंग का छोटा कुर्ता और ढीले-ढाले शरारा पैंट थे, जिन पर नाजुक सोने की ब्लॉक प्रिंटिंग और कढ़ाई की गई थी। इस लुक का सबसे खास तत्व एक पारंपरिक फुलकारी शैली का हाथीदांत रंग का दुपट्टा था, जिस पर भारी अलंकृत सोने की बॉर्डर बनी हुई थी, और जिसे उन्होंने पारंपरिक पंजाबी शैली में अपने सिर पर लपेटा हुआ था। उन्होंने अपने लुक को सुरुचिपूर्ण जातीय आभूषणों से पूरा किया, जिसमें पन्ना की बूंदों से सजा हुआ एक पारंपरिक पोल्की और कुंदन हार, मैचिंग स्टेटमेंट इयररिंग्स और सोने की चूड़ियाँ शामिल थीं। अपनी उपस्थिति के पीछे की प्रेरणा साझा करते हुए, गिल ने इस क्षण को कैप्शन दिया, पंजाब दी मिट्टी, कान्स दे कार्पेट ते (कान्स के कार्पेट पर पंजाब की मिट्टी) कान्स रेड कार्पेट पर पंजाब की ब्यूटी क्वीन सास- बहू की जोड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ एंट्री लेकर न सिर्फ ग्लैमरस रूप दिखाया, बल्कि उन्हें देखकर एक नजर में पहचानना भी मुश्किल हो गया कि कौन सास है और कौन उनकी बहू। दरअसल, मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 गीतांजलि ओमप्रकाश कान्स में अपनी बहू और यूएमबी मिसेज इंडिया 2025 डॉ. मेहर ओमप्रकाश के साथ आईं। जहां दोनों ब्यूटी टाइटल क्वीन का स्टाइलिश रूप देखने को मिला। एक ब्लैक ब्यूटी बन गईं, तो दूसरी ने सितारों से सजे गाउन में अपनी चमक बिखेरी। जिनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सास- बहू की जोड़ी ने रेड कार्पेट के लिए एक- दूजे से अलग लेकिन सेम वाइब वाले गाउन को सिलेक्ट किया। 79वें कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री मीत कौर ने अपने शानदार रेड कार्पेट लुक से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश प्रतिभा से मीत कौर ने ग्लोबल फैशन जगत और मीडिया का दिल जीत लिया। नेवी ब्लू और सिल्वर रंग के बेहद आकर्षक पुतले में नजर आईं मीत कौर ने आकर्षक फैशन और रॉयल एलिगेंस का बेहतरीन संगम पेश किया। डायमंड और ग्लैमरस स्टाइलिंग ने उनके पूरे लुक को एक प्रभावशाली कान्स फैशन मोमेंट बना दिया। अपने कॉन्फिडेंट वॉक और दमदार प्रेसेंस के साथ मीत कौर ने दुनिया भर में मशहूर हस्तियों और पार्टियों के बीच अलग पहचान बनाई।

उनका यह लुक सिर्फ ग्लैमर ही नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रतिभा और फैशन की बहु-पहचान को भी शामिल किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ पहले ही अपने हर शो में पंजाबी वेशभूषा और पगड़ी पहने पंजाबी संस्कृति को आकर्षण बरकरार रखे हुए हैं। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इन्हीं कलाकारों की बड़ी भूमिका रही है। कुल मिलाकर कान्स में इस

सम्पादकीय...

अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक निहितार्थ

लचीली भूराजनीति यानी फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स का जन्मदाता भारत को देखा-देखी अब पूरी दुनिया में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसे मोदी डॉक्ट्रिन कहना ज्यादा उचित होगा, जो गुटनिरपेक्षता का हाइब्रिड पॉलिसी संस्करण है। आम कहानी वाली भाषा में कहें तो खुल जा सिमसिम और बंद हो जा सिमसिम वाली वैश्विक कूटनीति ही अब लचीली भूराजनीतिक बन चुकी है। दरअसल, फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स यानी लचीली भूराजनीति का अर्थ ऐसी अवसरवादी विदेश नीति से है, जिसमें देश अपने हित के अनुसार कभी दोस्ती का दरवाज़ा खोलते हैं और कभी तुरंत बंद कर लेते हैं। आज की दुनिया में यही फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बढ़ रही है। जिसके सफल उपयोगकर्ता टीम पीएम मोदी हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत जैसे उन देशों को होता है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हों, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हों, सैन्य रूप से सक्षम हों, और बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन साधना जानते हों। यही वजह है कि भारत इसे अपनाकर दुनिया के शीर्षस्थ देशों की कतार में शामिल होने की दिशा में बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आखिर इससे किसका भला होगा? तो इसके कई जवाब होंगे, जिनमें पहला है महाशक्तियों का सबसे अधिक लाभ- संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और आंशिक रूप से रूस-भारत जैसी शक्तियाँ इस नीति से सबसे अधिक फायदा उठाती हैं। पूरक सवाल है क्यों? तो सीधा सा जवाब है कि वे परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बदल सकती हैं। आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और तकनीकी नियंत्रण का इस्तेमाल कर सकती हैं। मित्र और प्रतिद्वंद्वी दोनों से व्यापार जारी रख सकती हैं। उदाहरण- अमेरिका, चीन से प्रतिस्पर्धा भी करता है और व्यापार भी। चीन रूस का साझेदार है लेकिन पश्चिमी बाजार भी नहीं छोड़ना चाहता। वहीं, रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद एशियाई देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। दूसरा, मध्यम शक्तियों का भी फायदा- भारत, तुर्किये, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश मल्टी-अलाइनमेंट नीति से लाभ उठा रहे हैं। भारत इसका बड़ा उदाहरण है, जो क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी, रूस से रक्षा सहयोग भी रखता है, और अमेरिका से तकनीकी साझेदारी भी बढ़ाता है। इससे रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहती है, निवेश कई दिशाओं से आता है, और वैश्विक मंचों पर प्रभाव बढ़ता है। तीसरा, कॉर्पोरेट और टेक कंपनियों को बड़ा लाभ- एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियाँ देशों की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाती हैं। क्योंकि देश उन्हें निवेश आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट देते हैं, सप्लाई चेन अपने यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, और टेक्नोलॉजी कंपनियों को रणनीतिक साझेदार मानते हैं। सवाल है कि ऐसी मतलबी कूटनीति से नुकसान किसका? तो जवाब होगा कि- पहला, छोटे और कमजोर देशों का- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे एशियाई देशों पर दबाव बढ़ता है कि वे किसी एक खेमे का समर्थन करें। वे कर्ज जाल, प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, और सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच फँस जाते हैं। दूसरा, वैश्विक स्थिरता का- ऐसी कूटनीति में भरोसा कम होता है। देश स्थायी मित्र नहीं बल्कि तात्कालिक हित देखते हैं।

पश्चिम एशिया में नई ध्रुवीय राजनीति का उदय ?

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां कूटनीति, धर्म, सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक शक्ति संतुलन एक-दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं।इसी बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में है अब्राहम अकॉर्ड्स एक ऐसा समझौता जिसे अमेरिका ने इजरायल और अरब देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार कराया। अमेरिका और इजरायल इसे शांति, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हैं, जबकि ईरान और उसके समर्थक इसे मुस्लिम दुनिया को विभाजित करने और फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति मानते हैं। यही कारण है कि आज डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनेई के बीच वैचारिक और रणनीतिक टकराव खुलकर सामने आ रहा है। एक ओर ट्रम्प मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ जोड़कर एक नए पश्चिम एशियाई सुरक्षा गठबंधन का निर्माण करना चाहते हैं,तो दूसरी ओर मौजतबा खामेनेईअमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस्लामी एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस पूरे संघर्ष के पीछे केवल धर्म या विचारधारा नहीं,बल्कि तेल, व्यापार मार्ग,सैन्य प्रभाव, हथियारों का बाजार, चीन- रूस की बढ़ती मौजूदगी और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी छिपी हुई है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स केवल एक शांति समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई जियोपॉलिटिकल व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। साथियों, बात अगर हम अब्राहम अकॉर्ड्स को समझने की करें तो, यह वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में शुरू हुई द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है,जिसका उद्देश्य इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना था। 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दिसंबर 2020 में मोरक्को इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और सूडान ने भी सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की, हालांकि वहां की राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ गई। बाद में नवंबर 2025 में कजाकिस्तान ने भी औपचारिक रूप से इस समूह में शामिल होने की घोषणा की। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए ऐतिहासिक मानी गई क्योंकि 1994 में जॉर्डन और 1979 में मिस्र के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अरब देशों ने इजरायल के साथ खुले संबंध स्थापित किए।अब्राहम नाम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों की साझा सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को ध्यान में रखकर चुना गया, ताकि इसे धार्मिक टकराव के बजाय साझा विरासत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साथियों,अमेरिका और इजरायल को इस समझौते की आवश्यकता कई कारणों से महसूस हुई। सबसे बड़ा कारण था ईरान का बढ़ता प्रभाव। पिछले दो दशकों में ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और गाजा तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के जरिए तेहरान पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक चुनौतियां बढ़ा रहा था। अमेरिका समझता था कि यदि अरब देशों और इजरायल को एक साझा सुरक्षा ढांचे में नहीं जोड़ा गया, तो ईरान धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में प्रभावशाली शक्ति बन सकता है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स को एक प्रकार के एंटी-ईरान सुरक्षा गठबंधन के रूप में भी देखा गया। इजरायल के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उसे अरब दुनिया में वैधता मिली और उसकी क्षेत्रीय अलग-थलग स्थिति कमजोर हुई। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह समझौता पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने का साधन था, खासकर उस समय जब चीन और रूस धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति बढ़ा रहे थे। साथियों, इस समझौते का आर्थिक पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच समझौते के बाद व्यापार, तकनीक, रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, पर्यटन और निवेश में तेजी से वृद्धि हुई। इजरायल की हाई-टेक क्षमता और खाड़ी देशों की पूंजी ने मिलकर नए आर्थिक अवसर पैदा किए। खाड़ी देशों को इजरायल की जल प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी और रक्षा तकनीक तक पहुंच मिली, जबकि इजरायल को अरब बाजारों और निवेश का लाभ प्राप्त हुआ। अमेरिका ने भी इसे अपने आर्थिक हितों से जोड़ा क्योंकि इससे अमेरिकी हथियार उद्योग, ऊर्जा कंपनियों और तकनीकी निवेशकों को नए अवसर मिलने लगे। इस दृष्टि से देखें तो अब्राहम अकॉर्ड्स केवल राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक- सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा है।हालांकि, इस समझौते के आलोचक इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात मानते हैं। दशकों तक अरब देशों कीआधिकारिक नीति यह रही थी कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इजरायल के साथ पूर्ण संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। 2002 की अरब शांति पहल भी इसी सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स ने इस नीति को बदल दिया। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने फिलिस्तीन विवाद का समाधान हुए बिना ही इजरायल के साथ संबंध सामान्य कर लिए। इससे फिलिस्तीनियों में यह भावना पैदा हुई कि अरब दुनिया ने उनके संघर्ष को पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है कि ईरान, तुर्की, कतर और कई इस्लामी संगठन इस समझौते की आलोचना करते रहे हैं। साथियों, ईरान का विरोध केवल वैचारिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। तेहरान को डर है कि यदि सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश भी इस समझौते में शामिल हो गए, तो पश्चिम एशिया में एक ऐसा संयुक्त मोर्चा बन जाएगा जिसमें अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देश एक साथ खड़े होंगे। इससे ईरान की रणनीतिक घेराबंदी हो सकती है। यही कारण है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामेनेई लगातार मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने हाल के भाषणों में दावा किया कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं और अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। यह बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का संकेत भी है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह अभी भी क्षेत्रीय प्रतिरोध धुरी का सबसे बड़ा केंद्र है।दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड्स को अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में गिनते हैं। ट्रम्प प्रशासन की रणनीति यह रही कि अरब देशों और इजरायल के बीच संबंध सामान्य कराकर अमेरिका एक नया पश्चिम एशियाई ब्लॉक तैयार करे, जो ईरान और चीन दोनों के प्रभाव को सीमित कर सके। ट्रम्प चाहते थे कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश भी इस समझौते में शामिल हों। लेकिन यहां उन्हें कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब ने साफ कहा कि फिलिस्तीन के लिए एक अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय रास्ते के बिना वह इजरायल के साथ पूर्ण संबंध सामान्य नहीं करेगा। साथियों 27 मई 2026 को पाकिस्तान ने भी वैचारिक आधार पर इससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीनी मुद्दे से समझौता नहीं कर सकता। तुर्की और ईरान ने भी इसे मुस्लिम दुनियां को बांटने की अमेरिकी रणनीति बताया। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो देश अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं होंगे, वे अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार बन सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि अमेरिका ने किसी देश को केवल समझौते से बाहर रहने के कारण प्रतिबंधित नहीं किया है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में आर्थिक और सामरिक दबाव का इस्तेमाल करता रहा है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान पर भी समय- समय पर अमेरिकी दबाव दिखाई देता रहा है। हालांकि सऊदी अरब जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों पर सीधे प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजार और अमेरिकी हित दोनों प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी यह संभावना बनी रहती है कि जो देश अमेरिकी रणनीतिक ढांचे से बाहर रहेंगे, उन्हें रक्षा सहयोग, निवेश या कूटनीतिक समर्थन के मामलों में नुकसान सटीकता से झेलना पड़ सकता है। साथियों,अब्राहम अकॉर्ड्स के समर्थकों का मानना है कि यह समझौता पश्चिम एशिया को युद्ध और कट्टरता से निकालकर आर्थिक सहयोग और विकास की ओर ले जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि अरब और इजरायल आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर होंगे, तो संघर्ष की संभावना कम होगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी प्रश्न का न्यायपूर्ण समाधान नहीं होगा, तब तक कोई भी शांति स्थायी नहीं हो सकती। गाजा युद्ध और लगातार बढ़ते तनाव ने इस तर्क को और मजबूत किया है कि केवल आर्थिक समझौते क्षेत्रीय स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकते।आज पश्चिम एशिया दो बड़े वैचारिक और रणनीतिक ध्रुवों में बंटता दिखाई दे रहा है। एक ध्रुव अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी अरब देशों का है, जो सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक साझेदारी के जरिए नया क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना चाहते हैं। दूसरा ध्रुव ईरान और उसके समर्थक समूहों का है, जो इसे अमेरिकी वर्चस्व और इजरायली विस्तारवाद के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई मानते हैं। इस संघर्ष में चीन और रूस भी धीरे-धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

चीन खाड़ी देशों और ईरान दोनों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि रूस सीरिया और ईरान के माध्यम से क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अब्राहम अकॉर्ड्स केवल एक राजनयिक दस्तावेज नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का दर्पण बन चुका है। यह समझौता एक तरफ पश्चिम एशिया में नए आर्थिक अवसर और रणनीतिक गठबंधन पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ नए वैचारिक विभाजन और भू- राजनीतिक तनाव भी बढ़ा रहा है। ट्रम्प और मौजतबा खामनेई के बीच उभरता खुला टकराव इसी व्यापक संघर्ष का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि पश्चिम एशिया सहयोग और आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर वैचारिक ध्रुवीकरण और सैन्य प्रतिस्पर्धा के नए दौर में प्रवेश करेगा।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के बढ़ते साम्राय में पहचान बनाता जनपद बस्ती

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मुहिम के तहत अब केवल बड़े शहरों या प्रमुख धार्मिक केंद्रों तक ही पर्यटन को सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि ग्रामीण अंचलों को भी इसका मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नई पर्यटन नीति के माध्यम से गांवों में छिपी ऐतिहासिक कहानियों, पारंपरिक कलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य को पर्यटकों के सामने लाने की अनूठी पहल की गई है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के रूप में सामने आ रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ रही है। अयोध्या, काशी (वाराणसी) और मथुरा जैसे बड़े धार्मिक केंद्रों में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवास की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने होमस्टे नीति को विशेष बढ़ावा दिया है। इसके अंतर्गत गांवों में रहने वाले आम परिवारों को अपने घरों को पर्यटकों के अनुकूल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राज्य में अब तक 900 से अधिक होमस्टे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो पर्यटकों को न केवल ठहरने की बेहतर सुविधा दे रहे हैं बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अतिथि सत्कार संस्कृति से भी रूबरू करा रहे हैं।ग्रामीण जीवन को करीब से देखने और समझने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 'फार्म स्टे निवेश कार्यक्रम' की शुरुआत की है। प्रदेश के इतिहास में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसके तहत खेतों और ग्रामीण परिवेश को व्यवस्थित पर्यटन स्थलों के रूप में बदला जा रहा है। इस योजना का सीधा लाभ उन प्रगतिशील किसानों को मिल रहा है जो अपनी खेती के साथ-साथ पर्यटन को जोड़ रहे हैं। फार्म स्टे के माध्यम से पर्यटकों को कृषि पर्यटन, मधुमक्खी पालन, स्थानीय हस्तशिल्प को करीब से देखने और ग्रामीण जीवन की सादगी का सजीव अनुभव लेने का मौका मिल रहा है। प्रदेश सरकार के इन सभी प्रयासों के केंद्र में ग्रामीण क्षेत्रों के वे हस्तशिल्पी, कारीगर और छोटे व्यवसायी हैं जो सदियों से अपनी कला को संजोए हुए हैं। ग्रामीण पर्यटन की इन पहलों में पर्यटकों की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। जिन गांवों की पहचान उनके विशिष्ट हस्तकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं के लिए है, उन्हें विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को बाजार और आर्थिक सहायता प्रदान करना, पारंपरिक कौशलों को विलुप्त होने से बचाना और बाहर से आने वाले लोगों को एक बिल्कुल अनूठा और गहरा अनुभव प्रदान करना है। इससे युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है। पर्यटन के इसी जमीनी मॉडल को अमलीजामा पहनाने के लिए जनपद बस्ती में विशेष रूप से काम शुरू किया गया है। जिला प्रशासन ने इस मुहिम के तहत दो विशिष्ट गाँवों, बढ़नी मिश्र और अमोढ़ा खास को ग्रामीण पर्यटन विकास के लिए चिह्नित किया है। इन दोनों गांवों का चयन उनकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। बढ़नी मिश्र गाँव का अपना एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व है, जिसे रामायण कालीन भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि का मूल निवास माना जाता है। इसी पौराणिक जुड़ाव के कारण स्थानीय लोग इस पूरे क्षेत्र के प्राचीन नाम को वशिष्ठी के रूप में याद करते हैं। इसी क्रम में जनपद का दूसरा सुप्रसिद्ध अमोढ़ा खास गाँव अपनी ऐतिहासिकता एवं गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए अलग पहचान रखता है। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अमोढ़ा के राजा जालिम सिंह और उनकी पत्नी रानी तलाश कुंवरी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जमकर लोहा लिया था। इस ऐतिहासिक संग्राम के साक्ष्य के रूप में आज भी राजा जालिम सिंह के किले के अवशेष इस गाँव में मौजूद हैं। इसके अलावा, धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह गांव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग का प्रमुख पड़ाव राम रेखा मंदिर और चतुर्भुजी मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इन दोनों ऐतिहासिक गाँवों के स्थानीय निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को निखारने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा हस्तशिल्प पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण पहलों की शुरुआत की गई है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को मिल रहा है। वर्तमान में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम धरातल पर संचालित किए जा रहे हैं, और पर्यटकों के ठहराव के लिए होमस्टे सुविधाओं हेतु कुछ विशिष्ट स्थलों की पहचान भी कर ली गई है। इन प्रयासों से आने वाले समय में पर्यटकों को इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता का एक समग्र अनुभव मिल सकेगा।राज्य की इस विकास यात्रा को गति देने में 'नई पर्यटन नीति 2022' एक मजबूत आधार साबित हो रही है। इस नीति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के संगठनों और विभिन्न हितधारकों से मिले व्यावहारिक सुझावों को शामिल करके तैयार किया गया है। योजना के क्रियान्वयन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 'जिला संवर्धन परिषद' और 'नीति कार्यान्वयन समिति' को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत राजस्व, नगर विकास, आवास और स्थानीय स्वशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि विकास कार्यों को बिना किसी देरी के त्वरित गति से धरातल पर उतारा जा सके। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को 'प्रमुख पर्यटन स्थलों' के रूप में नामित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। अकेले बस्ती जिले में ही 'पर्यटन नीति 2022' के अंतर्गत अब तक लगभग 28 नई पर्यटन इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें होटल, बजट होटल, कन्वेंशन सेंटर और मार्गस्थ सुविधा केंद्र शामिल हैं। इन सभी निजी आतिथ्य इकाइयों में कुल मिलाकर लगभग 17415.93 लाख रुपये का भारी-भरकम निवेश प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र के इस निवेश से न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्थानीय संस्कृति, लोक कलाओं और क्षेत्रीय परंपराओं को एक बड़ा मंच देने के लिए लगभग हर जिले में 'महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे हैं। ये आयोजन पारंपरिक कला रूपों को जीवंत रखने में मददगार साबित हो रहे हैं, साथ ही उन कलाकारों की आजीविका का जरिया भी बन रहे हैं जो पीढ़ियों से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को बड़े स्तर पर पहचान मिल रही है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की इस कड़ी में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस, हर घर तिरंगा, संस्कृति उत्सव, नवरात्रि और वाल्मीकि जयंती जैसे बड़े आयोजनों को हर साल संस्कृति विभाग के माध्यम से विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन भव्य आयोजनों से न केवल सामाजिक समरसता और राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों में भी भारी उछाल आता है। इन उत्सवों के दौरान लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों से स्थानीय छोटे दुकानदारों, शिल्पकारों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधे तौर पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। राज्य सेक्टर की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों के बुनियादी विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2017 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पर्यटन विभाग ने अकेले बस्ती जिले के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों के कायाकल्प के लिए कुल 5180.87 लाख रुपये की भारी राशि स्वीकृत की है। इस भारी बजट से विकास की कुल 53 महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि शेष 7 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। इस वित्तीय सहयोग का सीधा लाभ उन लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिल रहा है जो हर साल इन स्थानों पर आते हैं। इस पूरी योजना के अंतर्गत जनपद के विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉकेटवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/[illegible])

सुबह आठ बजे बारिश के बीच भाटपाररानी पीएचसी पहुंचे डीएम, गायब मिले स्वास्थ्य कर्मी, तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

देवरिया।

सरकारी तंत्र को समयबद्ध और जन-उत्तरदायी बनाने की कड़ी में शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन की एक बड़ी सक्रियता सामने आई। तेज बारिश के बीच सुबह ठीक 08:03 बजे जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी भाटपाररानी तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। इस औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भारी अव्यवस्था और लापरवाही उजागर हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अख्तियार किया। अस्पताल में ओपीडी समय शुरू होने के बावजूद अधिकांश नियमित व संविदा स्वास्थ्य कर्मी और आरबीएसके की टीम मौके से नदारद मिली। इस घोर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कार्यप्रणाली की पोल तब खुली जब वहां प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला के साथ मौजूद आशा कार्यकर्ता का मदर-चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड अधूरा पाया

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का हुआ औचक निरीक्षण, प्रसव कराने आई महिला का एमसीपी कार्ड अधूरा मिलने पर भड़के डीएम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए मॉनिटरिंग के निर्देश, कस्तूरबा विद्यालय के टूटे शौचालय ठीक कराने और नियमित पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के आदेश

गया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि या तो धरातल पर आशा बहुओं की नियमित मॉनिटरिंग नहीं हो रही है या उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है।

उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी, एसीएमओ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने की सख्त हिदायत दी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगली बार निरीक्षण में यदि सुधार नहीं दिखा, तो सीधे कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को दवाओं का सुचारु वितरण और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत परखने के बाद जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, भाटपाररानी का रुख किया। वहां उन्होंने कक्षाओं में जाकर छात्राओं से सीधा संवाद किया, पठन-पाठन का स्तर जांचने के लिए सवाल पूछे और विद्यालय की सुविधाओं की जानकारी ली। छात्राओं की उपस्थिति को और बेहतर करने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में अनिवार्य रूप से नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित कराई जाए, ताकि अभिभावकों को सरकारी योजनाओं और शिक्षा के महत्व की जानकारी मिल सके। विद्यालय के निरीक्षण में छात्राओं के शौचालयों की टाइल्स टूटी-फूटी मिलने पर डीएम ने गहरी चिंता जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं को एक सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सके।

जनता दर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना की बाधा दूर करने का निर्देश, पढ़ाई छोड़ चुके 18 वर्षीय अनिल को दोबारा स्कूल भेजेगा प्रशासन

देवरिया। जिला मुख्यालय पर आयोजित नियमित जनता दर्शन के दौरान शुक्रवार को न केवल एक गरीब परिवार के आशियाने की राह आसान हुई, बल्कि आर्थिक तंगी के कारण अंधकार में जा रहे एक मेधावी युवा के भविष्य को भी नई रोशनी मिली। कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई के दौरान नगर पंचायत भलुअनी के जगर वार्ड नंबर-5 से आईं कलिंदी देवी पत्नी मोतीलाल ने जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के समक्ष अपनी गंभीर समस्या रखी। महिला ने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका पक्का मकान स्वीकृत हो चुका है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ तत्वों द्वारा विधिक निर्माण कार्य में जबरन अड़ंगा लगाया जा रहा है। इसके कारण किश्त मिलने के बावजूद निर्माण कार्य ठप पड़ा है। गरीब के आवास निर्माण में बाधा उत्पन्न किए जाने के इस मामले को जिलाधिकारी ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने बिना किसी विलंब के मौके से ही नगर पंचायत भलुअनी के अधिशासी अधिकारी से सीधे दूरभाष पर वार्ता की। जिलाधिकारी ने ईओ को निर्देशित किया कि वे राजस्व और पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर जाएं और विधिक रूप से स्वीकृत आवास के निर्माण में आ रही बाधा को दूर कर प्रकरण का पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित कराएं ताकि पात्र परिवार को समय से छत मिल सके। जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक दूसरा मानवीय पहलू तब सामने आया, जब जिलाधिकारी की नजर महिला के साथ आए उसके 18 वर्षीय पुत्र अनिल यादव पर पड़ी। जिलाधिकारी ने जब अनिल से उसकी शिक्षा के संबंध में आत्मीय पूछताछ की, तो युवक ने बताया कि उसने हाईस्कूल की परीक्षा तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन पारिवारिक विपन्नता और आर्थिक अभाव के कारण आगे की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इस व्यथा को सुनकर जिलाधिकारी ने अनिल की काउंसिलिंग करते हुए उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। माता कलिंदी देवी की सहमति मिलने पर जिलाधिकारी ने मौके से ही जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि वे अपनी देखरेख में अनिल का दाखिला जनपद के किसी प्रतिष्ठित विद्यालय में कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि पात्रों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ना जिला प्रशासन की नैतिक और शासकीय प्राथमिकता है।

इंसानियत की मिसाल- भटनी व देवरिया के युवकों ने दो साल से बिछड़े युवक को परिवार से मिलाया

भटनी देवरिया।

जिले में कुछ युवकों ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, जिसकी क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। झारखंड राय के कोडरमा जिले के संतगाव थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडिडीह निवासी धर्मेंद्र चौधरी पुत्र राजेंद्र चौधरी पिछले दो वर्षों से लापता था। वह देवरिया में रेलवे ट्रैक के किनारे भटकता हुआ मिला।

राकेश कुमार गोड़, अंगद, रविभूषण और मणि तिवारी की नजर युवक पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास

रेलवे ट्रैक पर भटक रहे झारखंड निवासी युवक को दिया सहारा, पुलिस से संपर्क कर परिजनों तक पहुंचाया

सुरक्षित रखा। दो दिनों तक उसकी देखभाल की, स्नान कराया और भोजन की व्यवस्था की। बातचीत के दौरान युवक के बारे में जानकारी मिलने पर युवकों ने झारखंड के

कोडरमा जिले के पुलिस कप्तान को फोन कर सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कप्तान ने संतगाव थाना पुलिस को निर्देशित किया, जिसके बाद युवक के परिजनों से संपर्क स्थापित हुआ। युवक के भाई ने फोन पर भावुक होकर कहा कि आप लोग भगवान के रूप में मिले हैं। आज के समय में ऐसे नेक दिल लोग बहुत कम मिलते हैं। आपका यह उपकार जीवनभर नहीं भूलेंगे।

बीएड द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न

101 में 99 प्रशिक्षु रहे उपस्थित, मेधावी छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन

भटनी देवरिया।

राम गुलाम राय पीजी कॉलेज बनकटा शिव सलक्षपुर देवरिया में शुक्रवार को बीएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2025-26 की प्रायोगिक परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा आंतरिक परीक्षक डॉ लक्ष्मी जायसवाल एवं वाह्य परीक्षक डॉ मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुई। इस दौरान बीएड विभागाध्यक्ष डॉ मनमोहन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ कविता मिश्रा, डॉ राहुल मिश्र एवं डॉ कमलेश मिश्र व के.डी. सिंह उपस्थित रहे। परीक्षा में कुल 101 छात्र-छात्राओं में से 99 प्रशिक्षु उपस्थित रहे। प्रकाश, अमरीष, फकरुद्दीन, प्रभात, अंकित, अनुराग, पवन, दिशा, नेहा, साधना, बेबी, अमृता, रिंकी, जूही एवं निशु सहित

कई प्रशिक्षुओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीएड विभागाध्यक्ष डॉ मनमोहन सिंह ने सभी प्रशिक्षुओं के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सफलता निरंतर मेहनत और प्रयास से ही प्राप्त होती है।

मुख्यमंत्री राय औद्यानिक विकास योजना के तहत कृषकों से आवेदन आमंत्रित

कुशीनगर।

उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री राय औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को विभिन्न मदों में लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी ने जनपद के इच्छुक कृषकों से आवेदन करने की अपील की है। प्राप्त लक्ष्य के अनुसार शाकभाजी उत्पादन हेतु 25 हेक्टेयर, बागवानी में मशीनीकरण के अंतर्गत ट्रैक्टर (2WD) का 01, पावर टिलर (08 बीएचपी तक) का 02, पावर टिलर (08 बीएचपी से अधिक) का 02 तथा पावर नैपसेक स्प्रेयर (12-16 लीटर) का 04 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य निदेशालय उद्यान, लखनऊ द्वारा पत्रांक 233/मुख्यमंत्री रा0औ0वि0 योजना/2026-27 दिनांक 25 मई 2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इच्छुक कृषक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय में संपर्क करें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम खतौनी (61 ख प्रमाण पत्र), दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। कृषकों का चयन प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित लक्ष्य की सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। योजना पूर्ण होने के बाद सत्यापन उपरांत अनुदान की धनराशि डीबीटी/काइंड डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, कुशीनगर से संपर्क कर सकते हैं।

भटनी की मस्जिदों में अदा हुई बक़रीद की नमाज़

कुर्बानी और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया ईद-उल-अजहा का पर्व

भटनी देवरिया।

नगर भटनी सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद-उल-अजहा (बक़रीद) का पर्व पूरे धार्मिक उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया। सुबह से ही नगर की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी तथा अल्लाह की राह में कुर्बानी दी। भटनी जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, नूरीगंज में 7 बजे तथा हतवा गांव में सुबह 7 बजे नमाज़ अदा की गई। नमाज़ के दौरान बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी नए और साफ-सुथरे कपड़ों में नजर

आए। कहीं कुर्ता-पायजामा तो कहीं पैंट-शर्ट पहने लोग ईदगाह और मस्जिदों की ओर जाते दिखाई दिए। नमाज़ के बाद लोगों ने घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की। पूरा नगर भाईचारे और सौहार्द के माहौल में डूबा रहा। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को बक़रीद की बधाई दी। त्योहार को लेकर नगर में उत्साह का माहौल बना रहा।

सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही पुलिस

बक़रीद के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए नगर की मस्जिदों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस कर्मी लगातार गश्त करते रहे और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखी।

सीबीएसई की कॉपियों में गड़बड़ी से मचा हड़कंप, ओएसएम पोर्टल पर पकड़े गए 20 मामले

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। इस साल पहली बार शुरू हुई इस डिजिटल जांच प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली के करीब 20 मामले सामने आए हैं। कई छात्रों ने जब पोर्टल पर अपनी स्कैन कॉपी देखी तो उन्हें पता चला कि दिखाई गई कॉपी उनकी नहीं है। इस खुलासे के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो बोर्ड को सफाई देनी पड़ी। अब पूरे सिस्टम की जांच कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, कक्षा 12 के छात्र वेदांत ने सबसे पहले आरोप लगाया था कि सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन प्रक्रिया में जो फिजिक्स की कॉपी अपलोड की, वह उसकी नहीं थी। छात्र ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी तो मामला तेजी से फैल गया। इसके बाद संजना समेत कई अन्य छात्रों ने भी ऐसे ही दावे किए। छात्रों का कहना था कि पोर्टल पर जो उत्तर पुस्तिका दिखाई गई, उसमें लिखावट और जवाब उनके नहीं थे। शिकायतें बढ़ने के बाद सीबीएसई ने संबंधित छात्रों से संपर्क किया और उनकी सही कॉपियां उपलब्ध कराईं। बोर्ड ने इन मामलों को टॉप प्रायोरिटी पर लेने की बात कही। सूत्रों के अनुसार, इस साल ओएसएम सिस्टम के तहत करीब 98 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गईं। कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ पन्नों की डिजिटल स्कैनिंग हुई। इतनी बड़ी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतें भी सामने आईं। जानकारी के मुताबिक, लगभग 68 हजार कॉपियों में स्कैनिंग क्वालिटी खराब मिली। इसके बाद इन कॉपियों को दोबारा स्कैन किया गया। हालांकि री-स्कैनिंग के बाद भी करीब 13 हजार कॉपियां तय मानक के मुताबिक साफ और पढ़ने लायक नहीं बन सकीं। ऐसी कॉपियों की जांच बाद में मैन्युअल तरीके से करनी पड़ी। मामले के सामने आने के बाद अब तकनीकी स्तर पर पूरे सिस्टम की जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी डीआईसीआई के विशेषज्ञ इस प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। टीम पोर्टल, स्कैनिंग प्रक्रिया और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की भी पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम के कोड और तकनीकी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि आगे ऐसी गड़बड़ियां न हों। दावा किया गया है कि अगले साल तक पोर्टल को पूरी तरह फ्लिप-फ्री बनाने की कोशिश होगी। सीबीएसई अधिकारियों ने नई तकनीक का बचाव भी किया है। उनका कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ती है और छात्रों को अपनी कॉपी देखने का मौका मिलता है। अधिकारियों के मुताबिक, तकनीक भविष्य है और आने वाले समय में इससे छात्रों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि अगले साल से छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं डिजिलॉकर में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी मार्कशीट के साथ छात्र अपनी स्कैन कॉपी भी देख सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि पहली बार किसी नई व्यवस्था को लागू करने में चुनौतियां आती हैं, लेकिन धीरे-धीरे सिस्टम मजबूत होगा। ओएसएम प्रक्रिया का ठेका देने को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक, तीसरी बार टेंडर जारी होने के बाद दो कंपनियां तकनीकी रूप से योग्य पाई गई थीं। इनमें कोएन्ट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस शामिल थीं। वित्तीय बोली में कोएन्ट ने प्रति उत्तर पुस्तिका लगभग 24.75 रुपये का रेट दिया, जबकि टीसीएस ने करीब 65 से 66 रुपये का रेट कोट किया था। इसके बाद कोएन्ट को ठेका दिया गया। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कंपनी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबेरेना के दौरान भी विवादों में रही है।

विपक्ष ने जांच की मांग क्यों उठाई?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने संवेदनशील काम का ठेका ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया, जिसका पुराना रिकॉर्ड विवादित रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। वहीं, सीबीएसई का कहना है कि तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है और छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने की है।

प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, बच्चों के भविष्य की नहीं - राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की गड़बड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, लाखों छात्रों के भविष्य की नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह पहले दिन से ही सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) और सीओईएमपीटी को अनुबंध दिए जाने के मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि देश के युवाओं को सच जानने का अधिकार है। गांधी ने खबरों को साझा किया और लोगों से उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सीबीएसई ने ओएसएम निविदाएं तीन बार आमंत्रित कीं। पहली बार एक भी बोली नहीं लगी। दूसरी बार कोई भी बोलीदाता पात्र नहीं पाया गया। और अंततः, तकनीकी मानकों को तब तक कमजोर किया गया जब तक कि सीओईएमपीटी उन्हें पार नहीं कर गई। स्कैनिंग रेजोल्यूशन कम कर दिया गया। रोबोटिक स्कैनर की अनिवार्यता हटा दी गई। सीएमएमआई प्रमाणन स्तर-5 से घटाकर स्तर-3 कर दिया गया। उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के लिए जुर्माने के प्रावधान भी हटा दिये गए। राहुल गांधी ने कहा, भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस ने भी तीसरे दौर में अर्हता प्राप्त की। लेकिन टीसीएस दौड़ में हार गई और सीओईएमपीटी-एक ऐसी कंपनी जिसका रिकॉर्ड विफलताओं से भरा रहा है-वह जीत गई। और आज सीबीएसई के छात्र किस बात की शिकायत कर रहे हैं? खराब तरीके से स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं, गायब पन्ने और एक खराब मूल्यांकन पोर्टल। गांधी ने कहा कि शिक्षकों ने सीबीएसई को चेतावनी दी थी कि ओएसएम प्रणाली को राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन से पहले कम से कम एक या दो साल की अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है, फिर भी इसे जल्दबाजी में लाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा, तो मैं फिर से पूछता हूं - कौन चाहता था कि सीओईएमपीटी जीते? किसने धीरे-धीरे मानकों को इतना कम किया कि यह कंपनी इसे पार कर सके? उन्होंने कहा, (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र) प्रधान जी और सीबीएसई का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। यह कोई जवाब नहीं है, यह जवाबदेही नहीं है। सवाल यह है कि क्या अनुबंध ईमानदारी से उस सर्वश्रेष्ठ कंपनी को दिया गया था जो काम को सही ढंग से कर सकती थी? गांधी ने कहा कि 18.5 लाख बच्चों का भविष्य एक ऐसी कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, जो केवल तब अर्हता प्राप्त कर सकी जब उसके लिए नियमों में ढील दे गई। उन्होंने कहा, सवाल पूछने के कारण मुझ पर हमला करने वाले भाजपा सरकार के मंत्रियों से- मैंने पहले दिन से ही स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की। इसे (जांच को) सीबीएसई से लेकर सीओईएमपीटी को दिए गए हर अनुबंध तक विस्तारित करें। हमारे युवाओं को सच्चाई जानने का हक है। गांधी ने कहा, मोदी जी, सीबीएसई की गड़बड़ी पर आपकी चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपकी निष्क्रियता देश को बताती है कि आपको वास्तव में किसकी परवाह है - लाखों छात्रों के भविष्य की नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सरकार के अस्तित्व की। कांग्रेस नेता गांधी ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अपनी पहले की बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें छात्रों ने पेपर लीक की घटना के बाद परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। राहुल गांधी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, नीट के छात्रों से मेरी मुलाकात के दौरान एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई- भारत के युवाओं का नरेन्द्र मोदी पर अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने मुझे बताया कि प्रश्नपत्र खुलेआम व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर बेचे जा रहे थे। उन्हें यह भी पता है कि ये किस कीमत पर बिक रहे थे, कौन इन्हें खरीद रहा था और यह माफिया कैसे काम करता है-इन बच्चों को यह सब जानकारी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास केवल एक ही सवाल था-अगर हमें यह सब पता है, तो सरकार और संस्थानों को क्यों नहीं? सच्चाई यह है कि ये बच्चे खुद सरकार से बेहतर समझते हैं कि इस खराब व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, और दूसरी ओर यह कितना शर्मनाक है कि सेना, जिसका काम देश को दुश्मनों से बचाना है, उसे आज मोदी सरकार बच्चों के पेपर को अपनी ही भ्रष्ट व्यवस्था से बचाने के लिए तैनात कर रही है। गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, अब केवल सतही सुधार से काम नहीं चलेगा। पूरे परीक्षा तंत्र को छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर शुरू से फिर से बनाना होगा। हम और बच्चों को नहीं खो सकते। और न ही एक भी पीढ़ी का भविष्य इस भ्रष्ट व्यवस्था के हाथों में छोड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि उनसे यह खुलासा हुआ है कि सीबीएसई ने इस साल की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली प्रदान करने वाले ठेकेदारों के लिए प्रस्तावों के वास्ते अपने अनुरोध में तकनीकी शर्तों को लगातार नरम किया।

राहुल गांधी नीट मामले को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे - भाजपा

नेशनल डेस्क । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नीट पेपर लीक मामले में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश कर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा की यह प्रतिक्रिया गांधी की उस टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस बयान को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया था कि सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी व्यक्तिगत रूप से नीट पेपर लीक की निगरानी की थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी को छात्रों के हितों की चिंता नहीं है और वह गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का उद्देश्य छात्रों का कल्याण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। त्रिवेदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने केवल पेपर लीक पढ़ा, मुद्दा शब्द नहीं पढ़ा। इससे पता चलता है कि वे बेखबर, मुद्दे से अनजान हैं।

ईरान ने ठुकराया ट्रंप का अनिवार्य अब्राहम समझौता- क्षेत्रीय शांति पर नया संकट, तेहरान-अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी

तेहरान । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ओर से अब्राहम समझौते के जबरन विस्तार की कोशिशों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने साफ किया है कि कोई भी शांति समझौता बाहरी दबाव के बजाय जमीनी हकीकत पर आधारित होना चाहिए। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने चेतावनी दी है कि बिना किसी ठोस भू-राजनीतिक आधार के थोपे गए समझौते सफल नहीं होंगे।

ट्रंप का फरमान और ईरान की दो टूक

हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट साझा की थी। इसमें उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों के लिए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बताया था। ट्रंप इसे तेहरान के साथ जारी गुप्त वार्ताओं के बीच एक महासमझौते के रूप में देख रहे हैं। राजदूत फतहली ने एएनआई से बात करते हुए इस अमेरिकी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिरता बाहरी ताकतों की ओर से निर्मित नहीं की जा सकती। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वहां की सरकारें आपस में सहयोग करें। उन्होंने इन समझौतों को शांति के बजाय केवल दिखाने का प्रोजेक्ट करार दिया। ईरान का मानना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश भी इस अमेरिकी दबाव से असहज हैं।

परमाणु समझौते की राह में अमेरिका बना रोड़ा?

एक तरफ ट्रंप इस विस्तार को युद्धविराम की पूर्व शर्त बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने कड़ा रुख अपनाया है। अराघची ने कहा कि अमेरिका को अपना विरोधाभासी रुख छोड़ना होगा। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल-बुसैदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अराघची ने कहा कि ईरान अपने वैध अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा।

पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही इस कूटनीतिक प्रक्रिया में 60 दिनों के एक समझौता ज्ञापन पर चर्चा हो रही है। इस समझौते के तहत ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने और परमाणु हथियारों की दौड़ से बाहर रहने की प्रतिबद्धता जतानी होगी। इसके बदले में अमेरिका ईरान की नौसैनिक घेराबंदी खत्म करने और उसकी जब्त संपत्ति को मुक्त करने पर चर्चा करेगा। हालांकि, ईरान ने ओमान को धमकाने और विरोधाभासी बयान देने के लिए अमेरिका की आलोचना की है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में ओमान की भूमिका

इस पूरे विवाद में ओमान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ईरान ने ओमान के सिद्धांतवादी रुख की सराहना की है, जबकि अमेरिका ने ओमान को ईरान के साथ टोलिंग सिस्टम में शामिल होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, बाद में बेसेंट ने यह भी बताया कि ओमान ने अमेरिका को आश्वस्त किया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। वर्तमान में ट्रंप इस पूरे मसले पर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक आपातकालीन बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं।

मौसम का मिजाज बदला- बिहार से बंगाल तक बरसा पानी, आंधी-बारिश के कहर में छह की मौत

नई दिल्ली । देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक ने लोगों को राहत भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले दो से तीन दिनों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार को तेज तूफान और भारी बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया। कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बंगाल में छह की मौत

कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मौसम अचानक बिगड़ गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। अलग-अलग हादसों में 6 जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, मौतें मकान गिरने, बिजली गिरने और करंट लगने की घटनाओं में हुईं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहीं।आंधी इतनी तेज थी कि कई इलाकों में बड़े-बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। कोलकाता और सॉल्ट लेक में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई जगह खड़ी गाड़ियों पर पेड़ों की शाखाएं गिर गईं। जानकारी के मुताबिक, कोलकाता और आसपास के इलाकों में करीब 36 पेड़ उखड़ गए।

किन राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ?

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी तेज धूल भरी आंधी आने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- यूपीएससी में कभी पेपर लीक नहीं हुआ

नई दिल्ली । नीट पेपर लीक मामले में पिछले 20 दिनों से देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य ने एनटीए को भंग करने के लिए याचिकाएं लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले पर कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं। कोर्ट में मौजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सवाल किया कि यूपीएससी तो आपसे बड़े पैमाने पर परीक्षा करवाता है, वहां कभी पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नीट पेपरलीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक न हो केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट-यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्योरा मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुधार किए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम युवाओं को लेकर गंभीर हैं। नीट-यूजी री-टेस्ट के लिए नए तरीके अपनाए गए हैं। देशभर में 3 मई को नीट-यूजी परीक्षा हुई थी। 7 मई की शाम पेपर लीक की खबर सामने आई थी। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को री-एग्जाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भंग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान 2024 में नीट पेपर लीक के बाद बनाई गई हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमुख और पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन से पूछा कि सिफारिशों और सुधारों के बावजूद इस बार नाकामी क्यों हुई।

पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत, आठ आरोपी गिरफ्तार

मुंबई । महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुणे के हडपसर में छह लोगों ने दम तोड़ा। फिलहाल आठ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और राज्य आबकारी विभाग ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने मुख्य आपूर्तिकर्ता योगेश वानखेड़े समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे सिटी पुलिस ने हडपसर थाने में आकाश जाधव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि योगेश वानखेड़े ने ही दोनों जगहों पर शराब की सप्लाई की थी। मामले में पुणे की उरुली कांचन पुलिस ने जहरीली शराब पीने से लगातार हुई मौतों के बाद शिंदेवाडे और भवरापुर में अवैध शराब की भट्टियों पर छापा मारा और एक लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त कर लिया। मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े ने अवैध देशी शराब का नशा बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिये मेथेनॉल खरीदा था।

पीड़ितों में एक से दिखे लक्षण

अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों में एक जैसे लक्षण देखे गए। उन्हें चक्कर आना, बेचैनी, मुंह से झाग निकलना और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें थीं। पुलिस को एक मृतक के शरीर में शराब के अंश मिले हैं। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी।

सीएम ने कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्तों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों शहरों की पुलिस को आपसी तालमेल के साथ जांच करने को कहा है। इस बीच, इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने हडपसर में अवैध शराब के एक ठिकाने को खुद नष्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मरने वालों की संख्या 18 है। उन्होंने गृह विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अवैध गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है।

दहेज लोभियों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार, कहा- जिनसे पैसे लेते हो, उन्हें ही भिखारी कहते हो

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान बेटियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले ससुराल वालों पर बेहद सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि शादी के बाद लड़की या उसके परिजनों को किसी की बेटी और उसके मायके वालों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि आप जिन लोगों से पैसे ऐंठते हैं, बाद में उन्हीं को भिखारी कहकर उनका अपमान करते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अब समाज में यह कड़ा संदेश जाना बेहद जरूरी हो गया है कि दुल्हन या उसके माता-पिता की बेइज्जती को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

अच्छे जजों को कूलिंग-ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं, कानून मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान

नई दिल्ली । केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सरकारी नियुक्तियों से पहले अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू करने की मांग को खारिज किया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ, निष्पक्ष और सक्षम है तो उसे काम करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है और इस पर कोई सर्वसम्मत दृष्टिकोण नहीं है। कूलिंग-ऑफ पीरियड वह निर्धारित समय होता है, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को अपने पद से रिटायर होने या इस्तीफा देने के बाद तुरंत किसी नई सरकारी, निजी या संवैधानिक नियुक्ति लेने की अनुमति नहीं होती।

पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में मेघवाल ने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि नियुक्तियों में देरी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न न्यायाधिकरणों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं और अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। कानून मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों में योग्य और अनुभवी न्यायाधीशों की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई सेवानिवृत्त जज न्यायसंगत सोच रखने वाला, स्वस्थ और सक्षम है तो उसकी नियुक्ति तुरंत करने में क्या समस्या है।

लंबे समय से किस बात पर बहस चल रही?

रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किए जाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी नियुक्तियां न्यायिक स्वतंत्रता और हितों के टकराव को लेकर सवाल खड़े कर सकती हैं। सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, भारतीय विधि आयोग और भारतीय प्रेस परिषद जैसी संस्थाओं में भी की जाती है। मेघवाल ने कहा कि कूलिंग-ऑफ पीरियड की मांग अक्सर इस धारणा पर आधारित होती है कि किसी जज को उसके फैसलों के बदले पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा मानना गलत है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां किसी विशेष फैसले के आधार पर नहीं की जातीं और इस तरह की आशंकाओं को राजनीतिक रंग दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन न्यायाधीशों का सेवा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उन्हें नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, सक्षम और प्रतिष्ठित जजों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि कई बार सेवानिवृत्त न्यायाधीश खुद भी नई नियुक्तियां स्वीकार नहीं करते और मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का काम करना पसंद करते हैं, जिसे अधिक लाभदायक माना जाता है। मेघवाल ने बताया कि देश में कुल 21 न्यायाधिकरण हैं और उनमें कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। सरकार सेवानिवृत्त जजों को इन पदों पर सेवा देने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन कई न्यायाधीश आर्बिट्रेशन कार्य को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि संविधान में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद किसी अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार पहले भी संसद में यह स्पष्ट कर चुकी है कि ऐसी नियुक्तियों का कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, क्योंकि केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने ढांचे के तहत नियुक्तियां करते हैं।